

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुयी मंत्रिमण्डल की बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना दो हजार छब्बीस सहित तीस महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। एक रिपोर्ट-

कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी उन्सठ हजार ग्राम सभाओं तक बस सेवा पहुंचाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में लगभग बारह हजार ग्राम सभाओं में बसें नहीं जा पा रही हैं, उन गांवों तक बस पहुंचाने का फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अट्ठाइस सीटों वाली छोटी बसें चलाई जायेंगी। श्री सिंह ने बताया कि अब ओला और ऊबर जैसी कम्पनियों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में पंजीकरण कराना होगा। परिवहन निगम एक ऐप भी बनायेगा, जिसमें ओला और ऊबर की गाड़ियों और उसके चालक की पूरी जानकारी होगी। कैबिनेट द्वारा स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी, जिसके अनुसार अब प्रापर्टी बेचने वालों की पहचान को खतौनी में देखा जायेगा। बिना मालिक्यत की जांच किये बगैर अब स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। राजस्व मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा। समाचार कक्ष से प्रेम चन्द्र गुप्ता।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रतिनिधिमण्डल ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर केन्द्र सरकार की ओर से जारी एयरोड्रम लाइसेंस प्रस्तुत किया। एयरपोर्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ श्नेलमैन सहित वरिष्ठ अधिकारियों के इस प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को परियोजना की प्रगति और आगामी चरणों के बारे में भी जानकारी दी।

पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने, आपूर्ति बनाए रखने, समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू किया है। एक रिपोर्ट-

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि आपूर्ति को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 100 प्रतिशत परिचालन उपलब्धता के अधीन बनाए रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि उर्वरक संयंत्रों को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 70 प्रतिशत के बराबर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गैस विपणन संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले चाय उद्योग, विनिर्माण और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 80 प्रतिशत के बराबर गैस की आपूर्ति बनी रहे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी शहरी गैस वितरण संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाली गैस उनकी पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत का 80 प्रतिशत हो। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल कहा कि भारत का रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्षेत्र विश्व के लिए देश की संस्कृति, खाद्य और सीधे स्थानीय विक्रेताओं या आस-पास के उत्पादकों से मिलने वाली ताजा वस्तुओं का प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास-जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार में यह बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रौद्योगिकी मीडिया मनोरंजन के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा रही है।

जो एंटरटेनमेंट और मीडिया की दुनिया है इस दुनिया में टेक्नोलॉजी का जो उपयोग अब इसको नैक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इसका पहला कैम्पस मुंबई में बन रहा है। इस टेंपरेरी कैम्पस में जो फौसिलिटीज बनीं जो ये ऐसे इंस्टीट्यूशनल चेन्स हैं, जो कि हमारे देश के युवाओं को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती हैं, जहां से स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ सकें और एकदम रेलीवेंट फील्ड में वो अपने को एक्सपर्ट बना के मार्केट में, दुनिया में अपनी पहचान बना सकें।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आगामी सब-इंस्पेक्टर-सिविल पुलिस और समकक्ष पदों के लिए आयोजित होने वाली सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नागरिकों के लिए एक समर्पित ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। बोर्ड के अनुसार परीक्षा सम्बन्धी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को लोग ई-मेल आईडी सतर्कता डॉट पुलिसबोर्ड एट दी रेट जी मेल डॉट कॉम और वाट्स एप नंबर नौ चार पांच चार चार पांच सात नौ पांच एक पर साझा कर सकते हैं।
